

.तारीख	हुबम या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील मे जारी हुए
08.06.2022	<p>वकुलाय फरिकेन उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्ट ने दिनांक 25.10.2021 को प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सैक्शन 96 सी पी सी पेश किया। रेस्पोजेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने दिनांक 10.05.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सैक्शन 96 सी पी सी प्रस्तुत किया। अभिभाषक अपीलान्ट ने दिनांक 23.05.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सैक्शन 151 सी पी सी प्रस्तुत कर प्रस्तुत कर अपील में किसी प्रकार की सुनवाई नहीं कर पत्रावली स्थगित रखने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलान्ट ने दिनांक 24.05.2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 1 रूल 10 (2) सी पी सी एवं सैक्शन 151 सी पी सी प्रस्तुत कर रेस्पोजेन्ट सं. 1 का नाम स्ट्रक ऑफ करने तथा शिक्षा विभाग व स्कूल के प्रधानाचार्य लौगेवाला का पक्षकार बनाने का निवेदन किया। रेस्पोजेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने दिनांक 24.05.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सैक्शन 151 सी पी सी किया, तथा दिनांक 31.05.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 1 रूल 10 (2) सी पी सी एवं सैक्शन 151 सी पी सी प्रस्तुत अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र विशेष कॉस्ट लगाकर खारिज करने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलान्ट ने प्राथमिक कानूनी आपत्ति अन्तर्गत सैक्शन 151 सी.पी.सी प्रस्तुत कर सरपंच लौगेवाला का नाम अपील से स्ट्रकऑफ करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्रों पर आज बहस सुनी गई।</p> <p>अपीलान्ट के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 1 रूल 10 (2) सी पी सी एवं सैक्शन 151 सी पी सी पर बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोजेन्ट सं. 1 सरपंच लौगेवाला अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था, प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार शिक्षा विभाग प्रधानाचार्य स्कूल व राजस्थान सरकार है, सरपंच लौगेवाला को भूलवशः व गलत रूप से पक्षकार बना लिया। अतः सरपंच लौगेवाला का नाम स्ट्रक ऑफ किया जावे शिक्षा विभाग व स्कूल के प्रधानाचार्य लौगेवाला को पक्षकार बनाने पर बल नहीं है। अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 2008 पृष्ठ 17-18, RRD 2002 पृष्ठ 130, RRD 2019 पृष्ठ 188, RRD 2011 पृष्ठ 778, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 पृष्ठ 120 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।</p> <p>अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सैक्शन 151 सी पी सी पर बहस के दौरान कथन किया कि प्रकरण में ग्राम लौगेवाला में माध्यमिक स्कूल हेतु खेल मैदान स्वीकृत हुआ। सरपंच लौगेवाला द्वारा जिला कलक्टर को पत्र लिखा गया कि उक्त खेल मैदान स्कूल से 1.5 किलोमीटर दूर होने से बच्चों को परेशानी होती है इसलिए स्कूल के नजदीक खेल मैदान हेतु भूमि आवंटित की जावे। जिला कलक्टर हनुमानगढ ने सरपंच की मांग पर स्कूल से 3 किलोमीटर दूर खेल मैदान हेतु भूमि आवंटित कर दी। सरपंच लौगेवाला द्वारा वहा पर अवैध रूप से भवन का निर्माण करवा लिया। ग्राम वासियो द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में सरपंच व विकास अधिकारी के विरुद्ध रिट पेश की। माननीय</p> <p>.....लगातार.....</p>	

उच्च न्यायालय ने दिनांक 24.01.2022 को आदेश पारित कर उक्त निर्माण को ध्वस्त करने हेतु जिला कलक्टर को आदेश दिये। उक्त आदेश के विरुद्ध सरपंच ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील पेश की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 09.05.2022 को मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत रखे जाने का आदेश पारित कर दिया। अतः अतः पत्रावली में किसी प्रकार की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक नहीं की जावे। पत्रावली व अपील स्थगित रखी जावे।

अभिभाषक अपीलान्त ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सैक्शन 96 सी पी सी पर बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार था, अपीलान्त वहा हाजिर भी हुआ था। ग्राम में स्कूल मैदान हेतु भूमि का आवंटन सार्वजनिक हित का मामला है, सरपंच को कोई समबन्ध नहीं होता है। अपीलान्त को धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र देने की जरूरत नहीं थी, फिर भी अपीलान्त ने अपील के साथ धारा 96 सी पी सी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, तथा अपीलान्त का आज भी उक्त भूमि पर कब्जा कारत है। इसके साथ अपीलान्त की अपील को दर्ज रजिस्टर कर स्थगन आदेश भी पारित किया जा चुका है। अतः रेस्पोजेन्ट के अभिभाषक की आपत्ति खारिज की जावे। अपीलान्त के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1978 पृष्ठ 482, RRD 2016 पृष्ठ 693, RRD 1995 पृष्ठ 179, RRD 1998 पृष्ठ 167, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

रेस्पोजेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 96 सी पी सी पर बहस के दौरान कथन किया कि आराजी जैर अपील राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज रही है। आराजीराज भूमि को आदेश जैर अपील से रा.उ.मा. वि. लौगेवाला के खेल मैदान हेतु आवंटन से अपीलान्त के किन्ही अधिकारो का हनन नहीं होता है। चक 3 एल.जी.डब्ल्यू के पत्थर नं. 47/284 के किला नं. 10 तादादी 0.253, किला नं. 11 तादादी 0.253, किला नं. 20 तादादी 0.253, किला नं. 21 तादादी 0.253, किला नं. 22 तादादी 0.253, दिनांक 14.02.1983 को दानाराम पुत्र खेताराम नायक निवासी लौगेवाला को उप जिलाधीश हनुमानगढ द्वारा आवंटित की गई। दिनांक 14.02.1983 को दानाराम पुत्र खेताराम को किये गये आवंटन के अपील गुरदयाल पुत्र गोविन्दसिंह द्वारा राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर कैम्प गंगानगर में प्रस्तुत की गई। जिसे दिनांक 20.03.1984 को स्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 14.02.1983 निरस्त कर दिया। आदेश दिनांक 20.03.1984 के विरुद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत हुई जो राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 17.01.1989 द्वारा खारिज कर दी। आदेश दिनांक 17.01.1989 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट प्रस्तुत हुई जो आदेश दिनांक 11.8.1997 द्वारा खारिज कर दी। उक्त आदेश के बाद दानाराम वगैरह ने एक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ में प्रस्तुत किया जो उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.11.1997 द्वारा खारिज कर दिया। दिनांक 15.11.1997 के उक्त आदेश के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में अपील प्रस्तुत हुई जिसे आदेश दिनांक 21.02.1998 द्वारा स्वीकार

.....लगातार.....

11
अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कर उपखण्ड को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन की कार्यवाही करने तथा कब्जाधारियों को बेदखल नहीं किया जाने का आदेश दिया। दिनांक 21.02.1998 के विरुद्ध सरकार द्वारा निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की जिसे दिनांक 27.05.2002 को स्वीकार करते हुए राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ का आदेश दिनांक 21.02.1998 निरस्त कर दिया। राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 27.05.2002 के विरुद्ध किसी भी पक्षकार ने कोई कार्यवाही नहीं की गई इसलिए राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 27.05.2002 अंतिम हो गया। राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर कैम्प गंगानगर द्वारा मूल आवंटन आदेश दिनांक 14.02.1983 अपने आदेश दिनांक 20.03.1984 से खारिज कर दिये जाने के बाद आराजी जैर अपील आराजीराज दर्ज है, जिसे अदालत मातहत ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आदेश जैर अपील से आवंटन की है जिसे अपीलान्त के किन्ही अधिकारो पर विपरित प्रभाव नहीं होता है। अपीलान्त को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। अतः अपीलान्त का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सैक्शन 96 सी पी सी खारिज कर अपील अपीलान्त खारिज की जावे। रेस्पोजेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1960 पृष्ठ 39, RRD 1969 पृष्ठ 192, RRD 1982 पृष्ठ 312-313, AIR 1979 S.C. का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

रेस्पोजेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 1 रूल 10 (2) सी पी सी एवं सैक्शन 151 सी पी सी बहस के दौरान कथन किया कि अपील के मामले में पक्षकार हेतु ऑर्डर 42 रूल के प्रावधान लागू होते हैं, ऑर्डर 1 रूल 10 (2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अपीलान्त ने अपील में ग्राम पंचायत को भूलवश पक्षकार नहीं बनाकर जानबुझकर पक्षकार बनाया है। अपीलान्त पत्रावली में बोगस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को उलझाये रखते हुए एक तरफा तौर पर स्थगन आदेश को कायम रखवाना चाहता है। अपीलान्त को आराजी जैर अपील राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को आवंटन होने की जानकारी थी इसके बावजूद अपील में कमी रखते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को पक्षकार नहीं बनाकर केवल ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया था, अब अपील में मियाद गुजर जाने के बाद ग्राम पंचायत को हटाकर शिक्षा विभाग व प्रधानाचार्य को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 रूल 10 (2) सी पी सी एवं सैक्शन 151 सी पी सी विशेष कॉस्ट लगाकर खारिज किया जावे।

रेस्पोजेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सैक्शन 151 सी पी सी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्त ने यह गलत कथन किया कि आराजी जैर अपील व आदेश के संबन्ध में कोई कार्यवाही ना तो उच्च न्यायालय के समक्ष जैरकार है ना ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलान्त द्वारा एकतरफा तौर पर प्राप्त स्थगन को अनुचित तरिके से कायम रखवाने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपील में अंकित भूमि व उच्च न्यायालय क निर्णय में अंकित भूमि अलग अलग

होने के कारण उच्च न्यायालय के निर्णय का आदेश जैर अपील पर कोई प्रभाव नहीं है। धारा 151 सी पी सी के तहत अपील स्थगित रखने का कोई प्रावधान नहीं है। अपीलान्ट स्वयं द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है तथा एकतरफा स्थगन प्राप्त किया गया है और अपीलान्ट स्वयं द्वारा ही अपील स्थगित रखने की मांग की जा रही है जो अपील लंबा खींचने के आचरण को स्पष्ट करती है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सैक्शन 151 सी पी सी विशेष कॉस्ट लगाकर खारिज किया जावे।

हमने प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 24.09.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। सर्वप्रथम धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना एवं पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में पक्षकार नहीं है किन्तु अपीलान्ट का अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में लम्बे समय तक विधिक कार्यवाही में भाग लिया जाना प्रथम दृष्टया साबित है। इस आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 रूल 10 (2) एवं उसके जवाब बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोजेन्ट सं. 1 अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम पंचायत लौंगेवाला के प्रस्ताव क्रमांक 26 दिनांक 05.03.2020 के अनुसरण में है। राजस्व विभाग व शिक्षा विभाग द्वारा खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन करने की कार्यवाही की गई। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत लौंगेवाला प्रथम दृष्टया हितबद्ध पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 रूल 10 (2) न्यायहित में खारिज किया जाता है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सैक्शन 151 सी.पी.सी. जवाब प्रार्थना पत्र बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला कलक्टर हनुमानगढ़ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2021 के क्रम में ग्राम पंचायत लौंगेवाला के पत्र क्रमांक 26 दिनांक 05.03.2020 के अनुसरण में उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के पत्र क्रमांक 431 दिनांक 13.03.2020 के द्वारा जिला कलक्टर हनुमानगढ़ से निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत लौंगेवाला के खेल मैदान को आबादी भूमि में परिवर्तन करने तथा उसकी एवज में विद्यालय से सटी हुई आबादी भूमि को खेल मैदान में परिवर्तन करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे। इस संदर्भ में ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति के द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई। परन्तु ग्राम पंचायत लौंगेवाला द्वारा पत्र क्रमांक 6-10 दिनांक 17.02.2021 को उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा से निवेदन किया गया कि मामला माननीय उच्च न्यायालय में डी.बी. सिविल रिट याचिका नं. 6557/2020 मनवीर सिंह व अन्य बनाम सरकार में श्री सुरेन्द्र थानवी को कोर्ट कमीश्नर नियुक्त किए जाने पर उन्होंने प्रस्तावित खेल मैदान की भूमि को उपयुक्त नहीं माना और 3 बीघा भूमि आवंटित करने के सुझाव दिए हैं। क्योंकि 3 बीघा भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में चक

.....लगातार.....

(५)

अति.संन्याय आयुक्त
दौकानेर

3 एलजीडब्ल्यू के पत्थर नं. 48/284 के किला नं. 3 ता 12, 18,23 एवं पत्थर नं. 47/285 के किला नं. 3 ता 7 कुल 3.795 हैक्टेयर(15 बीघा) भूमि रकबा राज उपलब्ध है जो कि विद्यालय से 1.5 कि.मी. दूरी पर है। उक्त प्रस्ताव पर तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा से रिपोर्ट ली गई। जिसके आधार पर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2021 को पारित किया गया है। अपीलान्त द्वारा धारा 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि पूर्व खेल मैदान को निरस्त किए बिना ही नवीन खेल मैदान आवंटन करने पर ग्रामवासियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में सरपंच एवं विकास अधिकारी के विरुद्ध रिट पेश की। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 24.01.2022 को अवैध निर्माण को ध्वस्त करने तथा रेस्पोडेन्ट सरपंच के विरुद्ध 50000 रु. का जुर्माना लगाया गया है। इसके विरुद्ध सरपंच द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील पेश की गई। जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिनांक 09.05.2022 को मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति रखने एवं दण्डात्मक कार्यवाही जारी रखने के आदेश दिए हैं। ऐसी स्थिति में जब तक खेल मैदान बाबत माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। पत्रावली बंद रखी जावे। प्रार्थना पत्र के समर्थन में डी.बी. सिविल रिट याचिका नं. 6557/2020 के आदेश दिनांक 24.01.2022 की प्रति प्रस्तुत की साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय एस.एल.ए. नं. 8655/2022 आदेश दिनांक 09.05.2022 की प्रति प्रस्तुत की। जिसके अनुसार अपील के लम्बित रहने के दौरान यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए गए हैं। अपने कथन के समर्थन में आर.आर.डी. 2010 पेज 556, आर.आर.डी. 2013 पेज 512 प्रस्तुत किए। जिसका अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वर्तमान खेल मैदान एवं अपीलाधीन आदेश से स्वीकृत किए गए खेल मैदान का सम्बन्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका नं. 6557/2020 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित एस.एल.ए. 8655/2022 से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में लम्बित एस.एल.ए. नं. 8655/2022 में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश है। इसलिए ऐसी स्थिति में अपीलाधीन खेल मैदान के सम्बन्ध में भी कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है इसलिए अपीलान्त के प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार करते हुए अपील अपीलान्त खारिज कर दाखिल दफ्तर की जाती है। माननीय उच्च न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार अपीलान्त आगामी कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र रहेंगे।

प्रति. ग्रामीय आयुक्त
कैकानेर